Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-I**

LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, November 28, 2024 / Agrahayana 7, 1946 (Saka)

HON’BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, November 28, 2024 / Agrahayana 7, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

MEMBERS SWORN	**1**
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 41 – 42)	**1A – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 43 – 60)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 461 – 690)	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, November 28, 2024 / Agrahayana 7, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, November 28, 2024 / Agrahayana 7, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 82**
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	**282**
4th Report	
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 21ST AND 28TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES – LAID	**283**
Shri V. Somanna	
MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON WAQF (AMENDMENT) BILL, 2024 – EXTENSION OF TIME	**283**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**284 - 93**
Shri Ramvir Singh Bidhuri	**284**
Shri Hasmukhbhai Somabhai Patel	**284**
Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava	**285**
Shri Ravindra Shukla *Alias* Ravi Kishan	**285**
Shri Rodmal Nagar	**285**
Shrimati Anita Subhadarshini	**286**
Shri Mitesh Patel (Bakabhai)	**287**
Shri Madhavaneni Raghunandan Rao	**287**
Shrimati Manju Sharma	**287**

Shri Ashok Kumar Rawat	288
Sushri Praniti Sushilkumar Shinde	288
Shri Brijendra Singh Ola	289
Adv. Dean Kuriakose	289
Adv. Adoor Prakash	290
Shri T.M. Selvaganapathi	290
Shri Eswarasamy K.	291
Shri Kesineni Sivanath	291
Dr. Alok Kumar Suman	292
Shri Selvaraj V.	292
Shri Hanuman Beniwal	293
…	294

xxx

(1100/PC/SMN)

1100 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

MEMBERS SWORN

KERALA

Shrimati Priyanka Gandhi Vadra (Wayanad)

MAHARASHTRA

Shri Chavan Ravindra Vasantrao (Nanded)

… (*Interruptions*)

1103 बजे

(इस समय श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब प्रश्न काल होगा। प्रश्न संख्या – 41 – श्री राम प्रसाद चौधरी जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रदीप पुरोहित जी।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 41)

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मान्यवर मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या बृजराजनगर में एनएच-49 पर चार लेन सड़क और आईबी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव है? … (व्यवधान)

इन परियोजनाओं के लिए कितना बजट आवंटित हुआ है? … (व्यवधान) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है? … (व्यवधान) यदि स्वीकृति नहीं हुई है, तो देरी और अस्वीकृति के क्या कारण हैं? … (व्यवधान)

(1105/SPS/SM)

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय स्पीकर महोदय, अकॉर्डिंग टू नेशनल हाइवे फी रूल्स हमारे यहां जो टोल प्लाजा है, इसमें काम पूरा हुआ है। … (व्यवधान) इसमें जो 60 किलोमीटर के बारे में जो बात कही गई है, उसमें बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को सेलेक्ट किया गया है।… (व्यवधान) इसके कारण उसके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।… (व्यवधान)

(इति)

(pp. 3-30)

(प्रश्न 42)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 42, श्री ए. मणि।

… (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। … (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं और अभावों को उठाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिया है और दूंगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है, उन पर चर्चा करने के लिए नियम और प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर देंगे तथा हर विषय पर देंगे, लेकिन गतिरोध का यह तरीका ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संविधान के 75 वर्षों के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, असहमति, सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। यह आपका मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। मैं आपको हर मुद्दे पर पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप चर्चा करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1108 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/RP/IND)

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock

(Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

1200 बजे

(इस समय श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): A few notices of Adjournment Motion have been received on different subjects. The hon. Speaker has disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

1200 hours

HON. CHAIRPERSON: Now, Papers to be laid on the Table.

Item No. 3 – Shri Suresh Gopi ji.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Amendment Regulations, 2024 (Hindi and English Version) published in Notification No. F.No. PNGRB/Fin/9-Gas Ex (2)/2021 Vol-IV (Part File-2) (E-4950) in Gazette of India dated 8th March, 2024 under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006.

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कैलेंडर वर्ष 2023 में प्रत्येक टाइप के सामान्य पूल रिहायशी आवास में होने वाली 5% रिक्तियों के लिए दिनांक 17.11.1997 के दिशा-निर्देशों के निबंधनों के अनुसार किए गए सामान्य पूल रिहायशी आवास के विवेकाधीन आउट-ऑफ-टर्न आवंटन के वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पिणयां।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
4th Report

1202 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to present the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

… (*Interruptions*)

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 21ST AND 28TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES - LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI V. SOMANNA): I beg to lay the following statements regarding: -

(i) the status of implementation of the recommendations contained in the 21st Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti.

(ii) the status of implementation of the recommendations contained in the 28th Report of the Standing Committee on Water Resources on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 21st Report of the Committee on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti.

… (*Interruptions*)

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON WAQF (AMENDMENT) BILL, 2024 – EXTENSION OF TIME

1204 hours

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to move the following motion: -

> "That this House do extend time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Waqf (Amendment) Bill, 2024 up to the last day of the Budget Session, 2025".

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That this House do extend time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Waqf (Amendment) Bill, 2024 up to the last day of the Budget Session, 2025".

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

1204 hours

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

Re: Deteriorating pollution condition and public transport system in Delhi

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं आपका ध्यान राजधानी दिल्ली में अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी प्रदूषण की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। राजधानी दिल्ली के लोग इस गंभीर स्थिति में जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, जिससे लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण के कारण दिल्लीवासियों की उम्र के 12 वर्ष कम हो रहे हैं। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पिछले दस सालों से दिल्ली की सड़कों की न तो कोई मरम्मत की गई है और न ही नई सड़कें बनाई गई हैं। सड़कों की धूल प्रदूषण लगातार बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलाने से किसानों को रोकने में पूरी तरह असफल रही है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली की जनता को इस भयंकर स्थिति से बाहर निकालने के लिए कदम उठाए।

(इति)

Re: Need to run Gujarat Sampark Kranti Express (train No. 12918) on daily basis

श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व) : मेरे संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद पूर्व (गुजरात) में लगभग 10 लाख से ज्यादा वैष्णव लोग रहते हैं। वैष्णव लोग मथुरा में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने जाते हैं। इन लोगों को मथुरा जाने के लिए हफ्ते में एक दिन गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12918) है। आपके माध्यम से मेरी माननीय रेलमंत्री जी से आग्रह है कि यह गुजरात संपर्क क्रांति ट्रेन (12918) हफ्ते में एक दिन की बजाय प्रतिदिन चलाई जाए जिसकी वजह से मेरे संसदीय क्षेत्र में भारी संख्या में रहने वाले वैष्णव जन को मथुरा जाने के लिए उचित रेल सुविधा मिल सके।

(इति)

Re: Need to increase the amount and number of scholarships disbursed to students on the basis of socio – economic background

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : देश में शिक्षा मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा छात्रों की मेरिट के आधार पर अथवा सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर दी जा रही विभिन्न छात्रवृत्तियों की धनराशि और संख्या दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है वर्तमान में मुद्रास्फीति की दर और जीवन यापन की लागत बहुत बढ़ गई है ऐसे में छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि उनकी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयुक्त है। इस संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल विभिन्न स्तरों पर इस बारे में मशविरा करें और आज की जरूरत के अनुसार छात्रवृतियों की संख्या और धनराशि बढ़ाया जाना सुनिश्चित करें।

(इति)

Re: Need to construct a Working Women's hostel in Gorakhpur Parliamentary Constituency

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर है। गोरखपुर में एयर फोर्स स्टेशन, हवाई अड्डा, विशाल रेलवे नेटवर्क और एम्स जैसा बड़ा असामान है। अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए गोरखपुर के आस पास के 20 जिलों के लोग गोरखपुर पर निर्भर है। गोरखपुर में बहुत बड़ी संख्या में कामकाजी महिलायें विभिन्नता स्थानों से आती हैं लेकिन उनके रहने के लिए एक वर्किंग वूमन हॉस्टल नहीं है जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से माँग करता हूँ कि कामकाजी महिलाओं के रहने के लिए गोरखपुर में 5 सौ कमरों वाला एक अत्याधुनिक वर्किंग वुमन हॉस्टल केंद्रीय सहायता से अविलंब बनाया जाए ताकि कामकाजी महिलाओं को इसका लाभ मिल सके और वे सुरक्षित और सुखी जीवन जीते हुए अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

(इति)

Re: Need to set up crop processing industries in Rajgarh Parliamentary Constituency

श्री रोडमल नागर (राजगढ़) : मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ (मध्य प्रदेश) अति पिछड़ा क्षेत्र था जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी से आशान्वित जिले में सम्मिलित कर मोहनपुरा ,कुंडालिया तथा रेशई-पार्वती डैम के साथ ही पार्वती -कालीसिंध-चंबल सिंचाई लिंक परियोजना से क्षेत्र में **6** लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित करने की दिशा में कदम बढ़ाये है। चार-चार राष्ट्रीय राजमार्गो एवं रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन की सौगात देकर राजगढ़ संसदीय क्षेत्र को विकासशील क्षेत्र की दौड़ में सम्मिलित किया है। मैं से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिन फसलों का उत्पादन हमारे राजगढ़**,** खिलचीपुर**,** ब्यावरा**,** सुसनेर**,** सारंगपुर**,** नरसिंहगढ़, चांचौड़ा एवं राघौगढ़ आदि स्थानो पर हो रहा है उनकी प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित कर औद्योगिक कॉरिडोर बनाने में सहयोग प्रदान करें।

(इति)

Re: Need for revival and upgradation of Aska Co-operative Sugar Industries Ltd. (ACSIL) at Aska, Odisha

SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): Aska Co-operative Sugar Industries Ltd (ACSIL) at ASKA in the State of Odisha needs an urgent financial package for the revival and the upgradation to meet its cost-effective production. It is one of the oldest Sugar Mills of Asia and nearly about 20,000 Sugarcane growers depend on this factory for their livelihood. The revival plan includes setting up of ancillary industries like – Ethanol plant, corrugated packing plant, Solar Power Grid 10 MW, and Fully automatic Mineral R.O. Plant. I urge upon the Central Government for the revival and upgradation of ACSIL during current financial year. If the sugar factory will be revived then sugarcane farmers will also be benefitted.

(ends)

Re: Need to grant Child Care Leave to male and female employees in uniform manner

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आणंद) : हमारे समाज में लंबे समय से यह धारणा रही है कि बच्चों की देखभाल मुख्य रूप से माताओं की जिम्मेदारी है। लेकिन यह सोच बदलने का समय आ गया है। छोटे परिवार और कम बच्चे पैदा करने के दौर वाले समय में यह अति आवश्यक हो गया है। पारिवारिक जिम्मेदारियां माता-पिता दोनों की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए, यह आवश्यक है कि बाल देखभाल अवकाश न केवल महिला कर्मचारियों को, बल्कि पुरुष कर्मचारियों को भी दिया जाए। इस कदम से न केवल पिता अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिता सकेंगे, बल्कि यह महिलाओं पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करेगा। यह समानता और साझा जिम्मेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमें याद रखना चाहिए कि एक बच्चे के विकास में माता और पिता दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल देखभाल अवकाश की सुविधा सभी सरकारी कर्मचारियों को, चाहे वे पुरुष हों या महिला, समान रूप से उपलब्ध हो।

(इति)

Re: Alleged illegal acquisition of land of farmers in Lagcherla village of Bomraspeta Mandal in Mahbubnagar district, Telangana

SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO (MEDAK): Massive land acquisition by Telangana Government at Lagcherla village in Bomraspeta Mandal, Mahbubnagar district, Telangana is being done without respecting the Land Acquisition Act, 2013. There is a state-wide agitation by farmers to suspend such motivated and dubious business deals. There is a repeat- offense in Telangana, where land is acquired for some stated high objectives and nothing materialises. In case of Lagcherla Land Acquisition, none of the norms and procedures of land Acquisition Act, 2013 have been followed. Farmers have been given an ultimatum in the same area, they are being evicted and harassed. There is urgency for Government to remind the Telangana Government to pause and properly judge the need of this Land. The intervention of Government of India is urgently sought to save the tribal farmers of Lagcherla. (ends)

Re: Maintenance and repair of city roads in States

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : अक्सर यह देखने में आया है कि देश में हर राज्य में शहरी सड़कों का रखरखाव, मरम्मत और देखभाल तीन एजेंसियों के माध्यम से होती है। वो है स्थानीय नगर निगम, स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य लोक निर्माण विभाग। वर्षा के बाद जब सड़कें खराब हो जाती है और जगह-जगह पर गढ्ढे हो जाते है. उन पर वाहन चलाना कठिन हो जाता है। उस समय कोई भी एजेंसी उन सड़कों को ठीक करने की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है। इससे आम नागरिकों को असहनीय परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कें खराब होने के कारण उन पर वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है और वाहन की क्षति होने की संभावना अधिक हो जाती है तथा ईंधन की खपत भी काफी बढ़ जाती है। इससे धन की हानि के साथ-साथ दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। यह समस्या न केवल मेरे प्रदेश राजस्थान में है, बल्कि देश के हर राज्य के शहरों की है. इससे निजात पाने की अति आवश्यकता है।

इस उपरोक्त कठिनाई और परेशानी से जो वहां की स्थानीय जनता को जूझना पड़ता है, इसको ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूँ जिससे कि इन कठिनाइयों और परेशानियों से स्थानीय जनता को कुछ राहत मिल सकती है। वो यह है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सभी राज्यों को यह निर्देश दे कि शहरी सड़कों की देखभाल, उनका रखरखाव और मरम्मत आदि का कार्य एक बोर्ड का गठन करके उसको सौंप दिया जाये। केवल वही बोर्ड शहरी सड़कों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लें। इससे शहरी सडको की हालत में सुधार होगा और जनमानस राहत की सांस ले सकेगा।

अत: मैं अंत में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि मेरी बात पर गहराई से चिन्तन करें और इस विषय में उचित कदम उठाएं जिससे कि स्थानीय जनता का भला हो सके।

(इति)

Re: Need to raise new army regiments on the basis of caste

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार के सैन्य अधिकारियों के द्वारा देश की सभी जातियों को योद्धा और गैर योद्धा जातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा 1857 तक जो भी जातियां ब्रिटिश प्रशिक्षित सैन्य बल में थी, उन्होंने ही उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने पासी, लोधी, निषाद, केवट, मल्लाह, राजपूत, कोली, मीणा, अहीर, त्यागी, गुर्जर, जाट, सैनी इत्यादि जातियों पर 12 अक्टूबर 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के माध्यम से रोक लगा दी। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 में सरदार वल्लभभाई पटेल ने इन जातियों को आपराधिक जातियों से मुक्त करके इनका सम्मान किया लेकिन अभी भी इन जातियों के सम्मान के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से गोरखा, जाट, महार, नागा, इत्यादि रेजीमेंट है, इस प्रकार से सातन पासी, जिन्होंने दलित और शोषित समाज में स्वाभिमान स्वावलंबन सह अस्तित्व की सुरक्षा के प्रति लोक और जागरूकता का साहसपूर्ण कार्य किया एवं पासी जाति और निषाद,लोधी, राजभर, मल्लाह इत्यादि जातियों के नाम से भी रेजीमेंट की स्थापना की जाय। मदारी पासी जाति को आने वाले चुनाव में प्रतिनिधित्व मिल सके।

(इति)

Re: Safety and security of women in Maharashtra

SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): An atmosphere of insecurity has enveloped women in Maharashtra as the incidence of crimes against women is rising in the State. NCRB data coupled with the recent cases in Badlapur, Indapur, Uran, and other parts of the State point towards a grim reality. This data shows an increasing trend in crimes against women in recent years, highlighting the urgent need for effective measures to ensure their safety and security. To put it into perspective, Maharashtra witnessed a 15% increase in crimes against women from 39,526 cases in 2021 to 45,331 cases in 2022. It topped the list for cases of harassment of women and incitement to suicide with 927 cases in 2022. Mumbai reported the highest number of molestation cases among major metropolitan cities with 1859 cases. Moreover, kidnapping of women in Maharashtra rose from 9,297 in 2022 to 9,698 in 2023. Rape cases saw a 6.2% rise from 7084 in 2022 to 7521 in 2023. It is hence urgent that the Government prioritise the safety and interests of women. It needs to seriously reflect on its approach to curbing violence and atrocities against women, as greater accountability is expected.

(ends)

Re: Need to address the problem of shortage of Urea and DAP in Rajasthan

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान किसानो से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण विषय की ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजस्थान सहित देश में वर्तमान में रबी की बुआई का समय चल रहा हैं। और किसानों को इस समय यूरिया , डीएपी खाद की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है, जिससे किसानो की बुआई प्रभावित हो रही है। साथ ही फसल में भी बिना यूरिया, डीएपी खाद के उत्पादन मे भी कमी आती है । आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि राजस्थान के शेखावटी सहित पूरे प्रदेश में किसानों को हो रही यूरिया, डीएपी खाद की किल्लत को अतिशीघ्र दूर करने की कृपा करें जिससे किसान आसानी से बुआई कर सकें।

(इति)

Re: Need to expedite approval to establish a Kendriya Vidyalaya at Thodupuzha in Idukki district, Kerala

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Idukki district, in my Parliamentary Constituency is one of the most backward districts in the state of Kerala. It is the long-standing demand of the people of Idukki that one Kendriya Vidyalaya be allocated at Thodupuzha. Thodupuzha fulfils all specifications for starting a new Kendriya Vidyalaya. Land is made available and a temporary building is now readied for starting the KV. All communications regarding the same has been submitted through the proper channel by the State Government. An inspection was conducted and completed with favorable report under the leadership of Deputy Commissioner, KVS, Kochi and other CPWD officers. They have given a go ahead and only a final approval is left. I humbly request and urge the Hon'ble Minister of Education to take steps to give the final approval for the project. This Kendriya Vidyalaya will fulfill the long-standing demand of the people of Idukki. It will also help thousands of children in achieving their lifelong dream of quality education at par with their peers elsewhere in the country.

(ends)

Re: Need to expedite completion of Nemom Railway Terminal Project in Thiruvananthapuram South, Kerala

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): I draw the attention of the House towards the ongoing development works of Thiruvananthapuram South (Nemom) railway terminal. After years of waiting, Railway Board had approved the project of Rs. 117 crore and the first phase of work has commenced. Original Master plan of Nemom Terminal included development of 5 Pit lines and 10 stabling lines. Now railways has cut short it to 3 Pit lines and 3 stabling lines. In order to get the aimed benefit, Thiruvananthapuram South must be developed as a full-fledged terminal. But there is no confirmation about the 2nd phase development works and even DPR has not been prepared. The cost estimated for the remaining works is around Rs.130 crores. The delay in second phase will cause the land value to shoot up and costs will be much higher than the current estimates. Moreover, it is necessary to complete the works as proposed to decongest Thiruvananthapuram Central station and to introduce new trains from the state's capital. So, I request the Government to kindly sanction the remaining work of 2 Pit lines and 7 stabling lines at Nemom urgently so that the entire work can be done together without causing cost escalation and inconvenience. (ends)

Re: Various demands of employees of Salem Steel Plant in Tamil Nadu

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): The employees of the Salem Steel Plant have been demanding an immediate resolution of their 14 demands which include 39 months of unpaid wages, overdue house rent payments that have accumulated over the past decade, an increase in salary, the continuation of the current grant-in-aid programme, updates to the incentive pay scheme that has not been revised since 2007, cancellation of mandates affecting work stoppages and changes, and a review of the bonus structure. The representatives from various Trade Unions had a meeting with the Chief Labour Commissioner in New Delhi on October 25, 2024, and requested him to address these 14 demands put forth by the workers. However, no productive resolution was reached at that meeting. Therefore, the employees were forced to go on a one-day strike on 28.10.2024. About 600 workers from across three units in the Steel Plant took part in the protest which affected the production of more than 1,500 tonnes. The unions have further warned to escalate their protests if the Union Government does not address their demands. Therefore, it is urged that the Government may look into this and redress the grievances of the agitating employees of Salem Steel Plant at the earliest. (ends)

Re: Need to provide better railway facilities at Pollachi Railway Station, Tamil Nadu

SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): The 100-year-old Pollachi railway junction, after a long struggle, has been converted into a broad-gauge railway line, with Coimbatore-Pollachi-Palakkad, Dindigul-Palani-Pollachi sections, and currently only a few trains are operating at the above junctions. Furthermore, Pollachi junction, which was considered a very important and historic railway station since the British era, is currently the terminal station of Salem, Madurai and Palakkad divisions without any importance.

This situation should be changed and converted into a railway station with all modern facilities, including a service station for maintaining train coaches, and an important railway station connecting the southern part of Tamil Nadu and the Konkan Railway operating in the western part. Pollachi should have daily passenger trains to important areas like Chennai, Thiruvananthapuram, and Rameswaram, and the Cheran Express train should be extended to Pollachi. Pollachi railway station should be connected to Salem or Madurai division. The closed booking counter should be opened. And the Vadukpalayam railway gate should be completely closed and after construction of the Foot over Bridge, it would be easier to cross the gate. Also, to improve freight traffic to Kochi, Thoothukudi, Chennai and the northern states. I request the Union Government to take steps. (ends)

Re: Need to provide additional 10-bedded Maternal and Child Health Care Centres in Rural PHCs in Vijayawada Parliamentary Constituency

SHRI KESINENI SIVANATH (VIJAYAWADA): In District Development Coordination and Monitoring Committee (DISHA) meeting held in NTR District, Vijayawada Parliamentary Constituency, on 05-11-2024, while reviewing on Medical & Health department, the need for additional 10 bedded Maternal and Child Health / care centres in Rural PHCs has been identified for which cadre strength to be sanctioned from National Health Mission. Total population under the 6 PHCs is 11,35,129, total pregnant women 17624 and child registrations 15247. It is also imminent that Institutional Deliveries need to be done in PHCs and as HR strength as appended is to be sanctioned by NHM with allocation of requisite funds. I request the Hon'ble Minister, Health and family Welfare to sanction the above at the earliest to promote 100% Institutional Deliveries in my Vijayawada Parliamentary Constituency.

(ends)

Re: Need to include and develop Thawe Junction Railway Station under Amrit Bharat Station Scheme

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : पूरे भारत में रेलवे ने 1318 स्टेशनों को आधुनिक एवं तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम में शामिल किया है। इसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के स्टेशन थावे जंक्शन को भी शामिल किया गया है। इस स्कीम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 अगस्त 2023 को किया था लेकिन थावे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अभी तक मास्टर प्लान नहीं बनाया गया है ताकि थावे जंक्शन का विकास यथाशीघ्र हो। अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी काम शुरू नहीं किया गया है जिससे कि लंबी दूरी या महानगरों के लिए ट्रेन का आवागमन नहीं हो पा रहा है। रेवेन्यू की भी क्षति रेलवे को हो रही है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के थावे जंक्शन स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मास्टर प्लान बनाकर काम जल्दी शुरू किया जाए ताकि थावे जंक्शन पर सारी जरूरी सुविधा यात्रियों को मिल सके। (इति)

Re: Need for permanent solution to the problems posed by Sri Lankan Navy for Indian fisherman

SHRI SELVARAJ V. (NAGAPATTINAM): The Indian fishermen are constantly facing assaults, pirate attacks, fines and humiliation at the hands of Sri Lankan Navy. In August, the Government had told the Parliament that 83 Indian fishermen were currently in judicial custody, 4 were serving sentences and 169 Indian fishing vessels had been seized. On September 14, five fishermen returned home to Pamban with their heads tonsured by Sri Lankan authorities for poaching in their territorial waters. They were released only after their families coughed up a fine of 50,000 Sri Lankan rupee. Their boats are not returned.

Lately, on November 10 Sri Lankan Navy apprehended 23 fishermen from Rameshwaram and seized their three boats. It is learnt that since January 2024, Sri Lankan Navy has confiscated 65 fishing boats and detained 485 fishermen. These fishermen are mainly from my Parliamentary Constituency Nagapattinam and Puthukottai districts of Tamil Nadu. There are complaints that the Indian Embassy in Sri Lanka is not providing any legal help to the detained fishermen.

Now a new regime has come to power in Sri Lanka. So, I request the Indian Government to initiate fruitful talks with the Sri Lankan Government to find a permanent solution to the problems of Indian fishermen.

(ends)

Re: Establishment of new Kendriya Vidyalayas in Nagaur Parliamentary Constituency

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : नागौर संसदीय क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय खीवसर, डीडवाना तथा परबतसर व नागौर जिले के ही मेडता उपखण्ड मुख्यालय पर नये केंद्रीय विध्यालयों की स्वीकृति करवाने तथा नागौर संसदीय क्षेत्र के ही मकराना,जायल व लाडनूं में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मंगवाने की मांग की तरफ शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिला कलेक्टर नागौर ने शिक्षा विभाग राजस्थान के माध्यम से खीवसर, डीडवाना तथा परबतसर मे नए के.वी. खोलने के लिए निर्धारित प्रपत्रों में केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किए थे तथा भौतिक निरीक्षण मे जो कमियाँ पाई गई उन कमियों को दूर करने हेतु जिला कलेक्टर नागौर ने 31 मार्च 2023 को कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया था। मेरा अनुरोध है कि नागौर जो दशकों से अच्छे शिक्षण संस्थानो की राह देख रहा है। ऐसे में निवेदन है कि केन्द्र सरकार खीवसर, डीडवाना तथा परबतसर व नागौर जिले के ही मेडता में नये केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति के सम्बन्ध मे वर्तमान स्थिति की जानकारी तलब करके केंद्रीय विद्यालय संघठन को जल्द से जल्द उक्त चारों स्थानो पर नए के.वी. की स्वीकृति करने व मकराना, जायल व लाडनूं में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव मंगवाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे। (इति)

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I request all the hon. Members to kindly return to their respective seats and allow the business to go ahead.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, kindly go back to your seats.

Shri Kiren Rijiju ji.

… (*Interruptions*)

(1205/RV/NKL)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सभापति महोदय, सारे विपक्ष के नेता और बिजनेस एडवाइज़री कमेटी के सारे मेम्बर्स ने, लोक सभा अध्यक्ष के साथ मिल कर, आने वाले हर बिल के लिए समय तय किया था और सभी मेम्बर्स ने एग्रीमेंट करके फैसला किया।... (व्यवधान) हर बिल को उचित समय देकर चर्चा करने का भी हम लोगों ने आग्रह किया था और एक्सेप्ट भी किया।... (व्यवधान) उसके बाद बाकी जो मुद्दे आने वाले हैं, उनके लिए भी चर्चा के लिए अलग-अलग नियम बने हुए हैं।... (व्यवधान) इस पर सबने एग्री किया है।... (व्यवधान) पर, यहां बिना रूल के, और अपने द्वारा ही बनाए गए रूल को तोड़ कर, कांग्रेस पार्टी और साथियों ने हंगामा करने की जो कोशिश की है, मैं इसकी निन्दा करता हूं।... (व्यवधान) यह सही नहीं है।... (व्यवधान) इस शीतकालीन सत्र को अच्छी तरह से चलाने के लिए सारे सदस्यों ने, जिनमें कई नए मेम्बर्स हैं, उन्होंने और पुराने मेम्बर्स, सबने कहा कि सदन में सभी को अपनी बात रखनी चाहिए, सदन में अपनी-अपनी कंस्टीट्युन्सी की बातों पर यहां चर्चा करनी चाहिए।... (व्यवधान) लेकिन, कांग्रेस पार्टी और साथियों ने इस तरह से हंगामा करके बाकी मेम्बर्स के अधिकारों का जो हनन किया है, उसका मैं खंडन करता हूं।... (व्यवधान)

महोदय, दूसरी बात है कि वक्फ़ (अमेंडमेंट) बिल को लेकर ज्वायंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनायी गयी।... (व्यवधान) विपक्ष की ओर से सारे मेम्बर्स ने रिक्वेस्ट की कि ज्वायंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो हियरिंग की है, उसको और समय चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।... (व्यवधान) हमने उसे भी एग्री किया।... (व्यवधान) पर, आज जब वक्फ़ (अमेंडमेंट) बिल के लिए बनी जे.पी.सी. के टाइम एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव मूव किया गया, तब भी खुद कांग्रेस पार्टी के लोग हंगामा कर रहे हैं।... (व्यवधान) यह गलत बात है।... (व्यवधान) मैं इसकी भी निन्दा करता हूं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 29 नवंबर, 2024 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1207 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 29 नवम्बर 2024/8 अग्रहायण 1946 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।